बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 14

खराब नजीर

राष्ट्रीय कंपनी ला अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने एक निर्णय में कहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) और उसके समूह की अन्य कंपनियों को कर्जदाताओं द्वारा तब तक गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पंचाट इसकी पूर्व मंजूरी नहीं दे देता। प्राथमिक तौर पर देखें तो एनसीएलएटी का गत सप्ताह दिया गया यह निर्णय आईएलऐंडएफएस तथा फंसे हुए कर्ज से जूझ रहे बैंकों, दोनों को राहत देता है। एनसीएलएटी के निर्णय में यथास्थिति निहित है जो कर्जदाताओं को यह मदद देगी कि उनका 53,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज फंसा हुआ कर्ज घोषित न हो। इससे उन्हें कम से कम फिलहाल तो प्रोविजनिंग से बचने का अवसर मिलेगा। परंतु, एनसीएलएटी को ऐसा निर्णय देने से पहले समुचित तरीके से विचार-विमर्श कर लेना था।

इस आदेश पर सवाल उठाने के कई आधार हैं और ये बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज की पहचान को लेकर एनसीएलएटी और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच संभावित विवाद की जमीन तैयार करते हैं। पहली बात तो यह कि एनसीएलएटी ने एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया है जो स्पष्ट रूप से देश के केंद्रीय बैंक के क्षेत्राधिकार में आता है। किसी ऋण को फंसा हुआ कर्ज माना जाए या नहीं यह निर्धारित करने का काम पूरी तरह उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। आरबीआई बीते तीन वर्ष से लगातार देश के बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज की पहचान और उसकी प्रोविजनिंग के लिए प्रयासरत है और एनसीएलएटी का यह निर्णय स्पष्ट तौर पर इन प्रयासों को सीमित करता है। ऐसे न्यायिक हस्तक्षेप से बचने की आवश्यकता है। इसमें दो राय नहीं है कि अगर देश का बैंकिंग क्षेत्र एनसीएलएटी का अनुसरण करता तो वह आरबीआई के परिसंपत्ति वर्गीकरण के नियमों का उल्लंघन होता। यह निर्णय आरबीआई के उस कदम के खिलाफ है जो वह नियामकीय सहनशीलता के खिलाफ उठा रहा है। ऐसे समय में जबकि आरबीआई की स्वायत्तता में निरंतर हस्तक्षेप हो रहा है, उसकी स्वायत्तता और प्राधिकार की दृष्टि से यह कदम कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यह आरबीआई के उन प्रयासों के खिलाफ है जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ऋण की वरीयता को नुकसान न पहुंचे। आरबीआई ने अतीत में जब यह कहा कि नियामकीय प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देनदारी में चूक की पहचान और प्रोविजिनिंग को डिफॉल्ट की वजह से अलग रखा जाए।

एक और वजह है जो आरबीआई के हस्तक्षेप की जरूरत बताती है। एनसीएलएटी का निर्णय सीधे तौर पर बैंक के आम जमाकर्ता के हित को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्योंकि फंसे हुए कर्ज की पहचान हो या नहीं लेकिन बैंकों को आईएलऐंडएफएस जैसे ऋण पर ब्याज नहीं मिलता है। इसका असर जमाकर्ताओं को मिलने वाले ब्याज पर पड़ता है। आरबीआई ऐसा नहीं होने दे सकता। दूसरी बात, यह आदेश आईएलऐंडएफएस के वित्तीय कर्जदाताओं के बीच भेद करता है। यह बैंकों को फंसे कर्ज की प्रोविजनिंग टालने का अवसर देकर राहत देता है जिससे उनकी बैलेंस शीट प्रभावित नहीं होती जबकि बॉन्ड धारकों और म्युचुअल फंड धारकों को यह सुविधा नहीं है। तीसरी बात, बैंक के भीतर भी यह आदेश बुरा संदेश देता है। यह उन बैंकों को दंडित करता है जो पहले ही आईएलऐंडएफएस को दिए फंसे कर्ज की प्रोविजनिंग कर चुके हैं। आदेश बैंकों को यह कहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कुछ नहीं हुआ है। अहम बात यह है कि यह कुछ बैंकों को तात्कालिक राहत ही देगा। यह मानना गलत होगा कि आईएलऐंडएफएस का मुद्दा अपनी तरह का इकलौता मामला है क्योंकि एनसीएलएटी का आदेश नजीर बन सकता है। आरबीआई अब तक खामोश है लेकिन वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे तो बेहतर होगा।

बिनय सिन्हा

इमरान के समक्ष विकल्प नेतृत्व करें या अनुसरण

बीते पांच दशक में पाकिस्तान का कद, उसे मिलने वाला समर्थन और उसका आर्थिक दर्जा, तीनों कमजोर पड़े हैं। बालाकोट के बाद इमरान खान के पास अवसर है कि वह हालात बदल सकें।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

आज अगर पाकिस्तान की बात आती है तो दो तरह की चुनौतियां सामने हैं। पहली बात, किस पर ध्यान दें इतिहास पर, भूगोल पर या फिर राजनीति पर? दूसरा आप इनमें से जो भी चुनें, शुरुआत कहां से करेंगे? मिसाल के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बाद मैं इस आलेख की शुरुआत 2019 से भी कर सकता था। या फिर 2009, 1999, 1989 या 1979 से भी। परंतु मैं आपको 1969 में लिए चलता हूं। हालांकि बहुत जल्दी ही मैं 2019 पर लौट आऊंगा।

सन 1967 में इजरायल ने मुस्लिम देशों को छह दिन के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। इन मुस्लिम देशों ने सन 1969 में इस्लामी सम्मेलन संगठन (ओआईसी) बनाने का निर्णय किया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन मंत्री (जो बाद में राष्ट्रपति बने) फखरुद्दीन अली अहमद को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख बनाकर भेजना तय किया। नाराज पाकिस्तान ने इसे रोकने का प्रयास किया और उसे इस्लामी दुनिया की सहानुभूति मिली। इस्लाम जगत ने यह दलील स्वीकार कर ली कि उस वक्त सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश के बिना कैसा ओआईसी? उस वक्त तक पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत को नकार दिया गया और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।

अब वापसी करते हैं 50 वर्ष बाद के समय यानी 2019 पर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ओआईसी की बैठक में माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां उन्होंने एक बेहतरीन भाषण दिया जिसमें कहा गया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भारत की विविधता का हिस्सा हैं और उनमें से 100 से भी कम ने आईएसआईएस में शिरकत की।

इसमें दो राय नहीं कि उनकी पार्टी द्वारा देश के मुस्लिमों को हाशिये पर धकेलने और अलग थलग करने तथा कश्मीरियों की दुष्ट छवि बनाने को लेकर कई वाजिब सवाल किए जाएंगे लेकिन कृपया इस बात की अनदेखी न करें कि एक हिंदू राष्ट्रवादी सरकार की शीर्ष महिला नेता दुनिया भर के मुस्लिमों के समक्ष उपरोक्त बातें कह रही है। विडंबना यह है कि भारत को दिए आमंत्रण के विरोध में पाकिस्तान ने आईओसी के आयोजन में शिरकत तक नहीं की। पांच दशक पहले पाकिस्तान के पास यह ताकत थी कि वह प्रमुख इस्लामी संगठन में भारत की उपस्थिति को वीटो करे। । आज वह केवल क्षुब्ध होकर बहिष्कार कर सकता है। पाकिस्तान जो 20 करोड़ की आबादी और नाभिकीय हथियारों और मिसाइलों के साथ खुद को इस्लाम का किला कहता है, उसकी इतनी दुखद स्थिति कैसे बनी?

अब 40 वर्ष पीछे चलते हैं, सन 1979 में। पाकिस्तान को सन 1971 की जंग में हार का सामना करना पड़ा था और उसके दो टुकड़े हो गए। वह अभी अपने आपको संभालने में लगा था। उसी वक्त सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे उसके साझेदार तथा चीन भी उस क्षेत्र में आ गए। जिसे अब अफ-पाक क्षेत्र कहा जाता है वह उस दौर का चर्चित युद्ध क्षेत्र था। पाकिस्तान उनका स्वैच्छिक और अनिवार्य सहयोगी बना। इसके बाद इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को नि:शुल्क और आसानी से हथियारबंद बनाने की शुरुआत हुई। इससे नए तानाशाह जिया उल हक मजबूत हुए और खुद को इस जिहाद का सच्चा कमांडर मानने लगे।

यह नई ताकत उनके सर चढ़कर बोलने लगी। उन्हें लगा कि अगर वे एक महाशक्ति के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारत के खिलाफ क्यों नहीं? भारतीय पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत सन 1981 में हुई। उसके अगले वर्ष वहां एके-47 और आरपीजी-7 ग्रेनेड लॉन्चर का आगमन हुआ। ये अफगान जिहादियों के इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार थे।

मेरी पहली पाकिस्तान यात्रा सन 1985 की गर्मियों में हुई जब यह सिलसिला जोर पकड़ रहा था। मैं इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले सिख अपहरणकर्ताओं के मामले की सुनवाई कवर करने गया था। मैं दोनों देशों के आम लोगों की समृद्धि, जीवन स्तर, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि दूरसंचार सेवाओं के स्तर में अंतर को देखकर अचंभित था। इंटरनेट के आगमन के पहले ये सेवाएं पत्रकारों के लिए ऑक्सीजन की तरह थीं। संक्षेप में सन 1985 में आम पाकिस्तानी, औसत भारतीय से बेहतर जीवन जीता था। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की प्रतिव्यक्ति आय भारत से 60 फीसदी अधिक थी।

एक बार फिर रुख करते हैं 2019 का। आज औसत भारतीय व्यक्ति किसी आम पाकिस्तानी की तुलना में 25 फीसदी अधिक कमाता है। आखिर कैसे पाकिस्तानी अपने इस नए भू राजनैतिक मूल्य के बावजूद न केवल 60 फीसदी की पुरानी बढ़त गंवा बैठे बल्कि 25 फीसदी और पिछड़ गए। यह अंतर सालाना 5 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से तीन फीसदी तेज गति से बढ़ रही है जबकि पाकिस्तान की आबादी भारत से दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। यह कैसे हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के खिलाफ 1,000 वर्ष तक जंग लड़ने की धमकी दी थी। परंतु सन 1969 के बाद के 50 वर्ष में ही पाकिस्तान का कद इस कदर घट चुका है कि इस्लामी जगत भी भारत को तरजीह दे रहा है। जिहाद को अपनाने के बाद के 40 वर्ष में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी है। पाकिस्तान ने भारत के साथ रक्त संघर्ष की केवल इतनी कीमत नहीं चुकाई है। यह सिलसिला जारी है। सन 1989 तक पराजित सोवियत संघ अफगानिस्तान से बाहर निकलने की शर्तों पर चर्चा कर रहा था। जीत के खुमार में पाकिस्तान ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाना शुरू कर दिया। यह लगभग वही समय था जब जम्मू कश्मीर में मौजूदा संकट की शुरुआत हुई। खाकी वर्दी वाले स्वयंभू गाजी अब वह जिहाद जीतने जा रहे थे जो उनके लिए वाकई मायने रखते थे। अगले तीन वर्ष जमकर खून खराबा हुआ। कश्मीर और पंजाब में हजारों लोगों की जान गई।

परंतु इस बीच पाकिस्तान में कुछ आंतरिक बदलाव आए। लोकतांत्रिक ताकतों ने वापसी की और जिया उल हक के वारिस राजनेताओं के साथ आंतरिक लड़ाई में उलझे रहे। नवाज शरीफ जो सेना के प्रिय थे, वह भी शांति की वकालत करने लगे। उन्होंने कश्मीर में अशांति फैलने के एक दशक बाद जनवरी 1999 में वाजपेयी के साथ शांति स्थापना की प्रक्रिया शुरू की। उनकी सेना ने उन्हीं दिनों करगिल में घुसपैठ की।

पाकिस्तान हार गया और दो बड़े बदलाव हुए। पहला, इस व्यापक वैश्विक दृष्टि का अंत हो गया कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। अब इस बात पर सहमति बनी थी कि नियंत्रण रेखा स्वत: सीमा है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी बात, उसी वर्ष पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का अंत हो गया। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया। उन 10 वर्षों में पाकिस्तान कश्मीर पर नैतिक रूप से भी कमजोर पड़ गया और सैन्य शासन की वापसी हो गई। इन सबके पीछे वही आत्मघाती रुख जिम्मेदार था। तब से अब तक काफी कुछ हो चुका है। 26/11 के आतंकी हमले ने उसे वैश्विक स्तर पर जिहाद के गढ़ का दर्जा दिलाया। करगिल के दौरान और संसद पर हमले के बाद दुनिया भारत के साथ हो गई क्योंकि उसने जिम्मेदारी का परिचय दिया।

आज भारत के प्रतिकार के बाद भी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उसके साथ हैं। बीते 50 वर्ष में पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया में अपना कद गंवाया। अब न सऊदी अरब उसके साथ है, न ईरान। बीते 40 साल में उसकी प्रतिव्यक्ति आय भारत की तुलना में 90 फीसदी तक गिरी। बीते 30 साल में भारतीय पंजाब और कश्मीर में उसे नाकामी हासिल हुई। उसके यहां जिहादियों का बोलबाला हुआ। बीते दो दशक में नियंत्रण रेखा स्वत: कश्मीर की सीमा बन गई। किसी के पास अब यह धैर्य नहीं था कि आतंक को नीतिगत उपाय के रूप में मान्यता दे। भारत ने पाकिस्तान में जो बमबारी की उसका किसी ने सांकेतिक विरोध भी नहीं किया। भारत और विश्व पाकिस्तान को ऐसा देश मानते हैं जो परमाणु हथियारों की शेखी बघारता है। इमरान खान अतीत का सिलसिला जारी रख सकते हैं या नई शुरुआत भी कर सकते हैं। यह जोखिम भरा होगा लेकिन इसमें सफलता की संभावना है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो दो बातों की गारंटी है: उनकी नाकामी और प्रतिभाशाली लोगों, मजबूत राष्ट्रवाद, उसकी ईश्वर प्रदत्त भौगोलिक स्थिति और मजबूत सेना के बावजूद देश का पराभव।

हमारे वक्त के दो गड़बड़ मुल्क पाकिस्तान और उत्तर कोरिया

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

मेरे मन में एक सवाल है जिसका उत्तर कतई आसान नहीं है। उत्तर कोरिया जो समूचे दक्षिण कोरिया पर दावा करता है, उसने पाकिस्तान की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया? पाकिस्तान भारत के एक अत्यंत छोटे से भूभाग पर लगातार अपना दावा करता आ रहा है। क्योंकि तमाम अन्य क्षेत्रों में उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच अलग करने जैसी कोई बात ही नहीं है। दोनों एक ही थैली के चट्टेबट्टे नजर आते हैं।

दोनों देश लगभग एक ही समय अपने औपनिवेशिक शासकों से आजाद हुए। कोरिया को 1945 में आजादी मिली और पाकिस्तान का निर्माण सन 1947 में हुआ। दोनों का जन्म बंटवारे की वजह से हुआ। एक विभाजन साझा लेकिन अनिच्छा भरी सहमति से हुआ। दूसरे के लिए अमेरिका और रूस ने मजबूर किया।

ब्रिटिश शासकों को लगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपना-अपना शासन संभाल सकते हैं जबकि रूस और अमेरिका को लगा कि कोरिया स्वशासन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में ब्रिटिश शासक भारत और पाकिस्तान को तो उनके भरोसे छोड़ गए लेकिन रूस और अमेरिका ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अपने-अपने संरक्षण में ले लिया। बाद के दिनों में जहां भारत और दक्षिण कोरिया में स्वशासन की काबिलियत नजर आई, वहीं पाकिस्तान और उत्तर कोरिया में यह क्षमता उस कदर नहीं नजर आई।

पाकिस्तान ने भारत से विभाजन के दो महीने के भीतर ही युद्ध का आगाज कर दिया। उत्तर कोरिया ने 1950 में दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध शुरू कर दिया। सन 1953 में उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा और सन 1953 में ही कोरिया का औपचारिक विभाजन पूरा हुआ। ठीक यही बात पाकिस्तान के साथ घटित हुई और वह 1971 में दो टुकड़ों में बंट गया।

दोनों कोरिया के बीच अब असैन्य क्षेत्र (डीएमजेड) है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा या एलओसी है। रूस ने उत्तर कोरियाई सेना को प्रशिक्षित किया और उसे हथियार दिए। उसने उन्हें परमाणु तकनीक भी उपलब्ध कराई।

अमेरिका उस हद तक तो नहीं गया लेकिन उसने भी पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए। सन 1980 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा था तब भी अमेरिका ने अपनी आंखें मूंदे रखीं।

सन 1990 के दशक में रूस ने उत्तर कोरिया का साथ छोड़ दिया और सन 1990 के दशक में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को त्याग दिया। दोनों की वजह एक ही थी। उन्हें ये देश मुसीबत नजर आने लगे थे।

अमेरिकी दबाव से मुक्त होने के बाद पाकिस्तान ने सन 1998 में परमाणु परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने 2006 में यह परीक्षण पूरा किया। आज दोनों चीन के संरक्षण में हैं। इन दोनों देशों के खिलाफ किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय सहयोग की स्थिति में चीन अपने वीटो अधिकार का प्रयोग करता है। उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी कोई अच्छी नहीं है।

परंतु दोनों के बीच समानताओं का सिलसिला वहीं समाप्त हो जाता है। उत्तर कोरिया ने शुरुआत में कुछ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया लेकिन 1983 में उसने इनसे निजात पा ली। पाकिस्तान ने उसी साल अक्टूबर महीने में उसने इसका आगाज किया।

उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कुछ अवसरों पर असैन्यीकृत सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया। उसने पश्चिमी सागर में उत्तरी सीमा का भी उल्लंघन किया। परंतु पाकिस्तान ने ऐसी हरकत कई बार की। उसने एक बार नहीं बल्कि चार अवसरों पर नियंत्रण रेखा पर लड़ाई तक छेड़ दी। इस मानक पर तो पाकिस्तान उत्तर कोरिया से मीलों आगे नजर आता है।

उत्तर कोरिया की सेना को यह पता है कि उसकी सीमा क्या है और वही उसी अनुरूप व्यवहार करता है। पाकिस्तानी सेना किसी सीमा को नहीं मानती है और वह जहां अवसर मिलता है वहां खुराफात कर बैठती है।

एक अंतर यह है कि पाकिस्तान अपनी सरकार के प्रमुखों का चुनाव निर्वाचन के माध्यम से करता है जबकि उत्तर कोरिया में यह आनुवांशिक तरीके से होता है। परंतु दोनों देशों की असली ताकत उनकी सेना में निहित है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष को नियुक्त करता है लेकिन उस पर नियंत्रण उसी सेनाध्यक्ष का होता है। उत्तर कोरिया में सबकुछ वहां के शासक के हाथ में है लेकिन वहां भी सेना की ताकत ही सर्वोपरि है। अगर सेना चाहे तो उसे एक क्षण में हटा सकती है।

पाकिस्तान में सक्रिय राजनीति है, जीवंत नागरिक समाज है, एक हद तक स्वतंत्र मीडिया और अच्छी न्यायपालिका भी है। उत्तर कोरिया में इसका ठीक उलट सच है। पाकिस्तान के लोगों में हास्यबोध है जबकि उत्तर कोरिया में तो किसी के नागरिक के हंसने तक पर उसके नेता का ही अधिकार है।

एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान से लाड़ लड़ाता था और उत्तर कोरिया के साथ किसी उपद्रवी की तरह व्यवहार करता था। अब मामला एकदम उलटा हो चुका है। उत्तर कोरिया को अमेरिका समेत सभी देशों द्वारा उसके 65 साल के निर्वासन से उबारा जा रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका समेत ये सारे देश पीछे धकेल रहे हैं। रूस अतीत में हमेशा पाकिस्तान की अनदेखी करता आया, अब वह उसे अलग-थलग करने की कोशिश का विरोध कर रहा है। वहीं चीन पुराने रिश्तों में नई जान फूंकने की कोशिश में लगा हुआ है।

इन बातों को लेकर हर किसी के मन में बुरी भावना है पाकिस्तान और उत्तर कोरिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि अन्य देशों में जहां देश के पास सेना होती है वहीं पाकिस्तान और उत्तर कोरिया में सेना के पास मुल्क है।

कानाफूसी

घटनाप्रधान महीना

मार्च का महीना आरंभ हो गया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि आखिर आम चुनाव की तारीख कब घोषित की जाती हैं। पुराने कार्यक्रम के मुताबिक तो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को 5 और 6 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था ताकि वहां चुनावी तैयारियों पर नजर डाली जा सके। इसके बाद 9 मार्च को चुनाव के बारे में अगली घोषणा की जानी थी। परंतु पुलवामा कांड के बाद बालाकोट में भारत के हवाई हमले के बाद हालात बदल गए हैं। सवाल यह है कि क्या अब भी निर्वाचन आयोग वहां जाएगा? सन 2004 में चुनाव की तारीख की घोषणा 6 मार्च को की गई थी और उसके तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह घोषणा अब किसी भी समय हो सकती है। मार्च में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहली किताब भी आने वाली है। इस किताब का नाम है, 'अगेंस्ट आउटरेज'। इस किताब का मसौदा तक किसी ने नहीं देखा है लेकिन यह किताब महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

आपका पक्ष

देश का जांबाज वीर अभिनंदन

देश के जांबाज सिपाही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान आखिरकार देश वापस लौट आए हैं। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम इंडिया की जर्सी वाली एक तस्वीर जारी की, जिस पर विंग कमांडर अभिनंदन और नंबर-1 लिखा है। बीसीसीआई ने यह जर्सी अभिनंदन के सम्मान में जारी की है। बीसीसीआई ने जर्सी वाली तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की और लिखा, 'वेलकम होम अभिनंदन। आप आकाश में राज करते हैं और आप हमारे दिलों पर राज करते हैं। आपका साहस और गौरव टीम इंडिया की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे।' सोशल मीडिया पर बीसीसीआई से इस जर्सी को अभिनंदन को सौंपने की अपील की गई है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी देशवासियों ने पाकिस्तान से उनकी वापसी पर खुशी जाहिर की है। अभिनंदन ने

पिछले सप्ताह अदम्य साहस का परिचय देते हुए मिग 21 विमान से पाकिस्तान के एफ-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान में आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत ने यह कार्रवाई की थी। वहीं, पुलवामा आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को एक पत्र लिखकर आईसीसी और उसके सदस्य राष्ट्रों से आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों से संबंध खत्म करने की मांग की थी। हालांकि आईसीसी ने कहा कि इस तरह के मामलों में उसकी की कोई भूमिका नहीं है और किसी देश से क्रिकेट संबंधी रिश्ते तोड़ना उसके दायरे में नहीं है। लेकिन पुलवामा हमले के बाद पूरे विश्व को यह समझना होगा कि आतंकवाद का कोई देश या मजहब नहीं होता। यह सभी अमानवीय सीमाओं से परे है और इस सुंदर संसार को विकृत करता जा रहा है। विश्व के सभी देशों को एक साथ आकर इसके खिलाफ एकजुट होना होगा वरना बहुत अधिक देर हो जाएगी शायद आतंकवाद एक अनचाही वास्तविकता बन जाएगा।

बीसीसीआई ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए नंबर-1 लिखी जर्सी जारी की है

दिव्या सिंह, नई दिल्ली

धोखाधड़ी के नए तरीकों से बचें

आजकल साइबर धोखाघड़ी के लिए कई नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई हैकर किसी तरह पहले आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कराते हैं और इसके जरिये वे व्यक्ति के फोन तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। इससे बाद हैकर कई तरीकों से मोबाइल या वॉलेट संबंधी लेनदेन को अंजाम देता है। एक अन्य मामले में हैकर ने किसी व्यक्ति का खाता हैक करके राशि दूसरे व्यक्ति के खाते में भेज दी और उस दूसरे व्यक्ति से बैंक एटीएम खराब होने का बहाना बनाकर नगदी ले ली। ऐसे में दूसरा व्यक्ति इस मामले में फंस गया और पुलिस इसका संज्ञान ले रही है। आजकल धोखेबाज फोन कॉल करना, ओटीपी मांगना जैसे पुराने तरीकों को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। वे अब प्रलोभनों के स्थान पर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें लोगों की गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करने वाला तरीका भी शामिल है। अगर समय रहते हमने बैंक या आरबीआई को नहीं बताया तो पूरा घाटा आपको खुद उठाना होगा। हमें इन मामलों में अधिक सतर्क रहना होगा और ऑनलाइन लेनदेन के समय सावधानी बरतनी होगी।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।